कि स्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कई राज्यों में व्याप्त बिजली संकट को सामने रखते हुए बिहार राज्य अन्तर्गत नालन्दा जिला में थरमल पावर स्टेशन स्थापित करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (287)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश के किसानों की दयनीय अवस्था को देखते हुए सिंचाई की विस्तृत योजनाओं की चर्चा नहीं की गई है जिसमें प्रत्येक पंचायत में कम से कम तीन राजकीय नलकूप की व्यवस्था हो।" (288)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अन्तर्गत प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने का ठोस कार्यक्रम का वर्णन नहीं किया गया है।" (289)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राचीन एतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान राजगृह और नालन्दा के अपेक्षित विकास के लिये ठोस एवं विस्तृत कार्यक्रम की चर्चा नहीं की गई है।" (290)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद की बात है कि देश में न तो रेल मार्ग के व्यापक विस्तार करने की चर्चा की गई है और न बिहार राज्य में स्थित बख्तयारपुर राजगीर तक की रेल लाईन को गया तक बढ़ाने का उल्लेख किया गया है।" (291)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि के विकास के लिये तथा किसानों को आधुनिक कृषि ज्ञान से पूरी तरह लैस करने के लिये देश के तमाम जिला मुख्यालयों में मिट्टी जांच करने तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की कोई चर्चा नहीं की गई है।" (292)

15.30 hrs.

REVOCATION OF PROCLAMATION *RE* STATE OF KERALA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Mr, Speoker, Sir, with your permission I beg to lay on the Table a copy of the Proclamation (Hindi and English versions) dated the 25th January, 1980 issued by the President under clause (2) of article 356 of the Constitution revoking the proclamation issued on the 5th December, 1979 in relation to the State of Kerala, published in Notification No. G.S.R: 17(E) in Gazette of India dated the 25th January, 1980, under article 356(3) of the Constitution.

15.32 hrs.

RESOLUTION *RE* SETTING UP OF A PETRO CHEMICALS UNIT AT BEGUSARAI (BIHAR)

MR. SPEAKER: Now we proceed with the Private Members' business. Before we take up the resolution of Smt. Krishna Sahi for discussion we have to fix time for this resolution. Shall we fix two hours?

SOME HON'BLE MEMBERS: Yes. The second resolution is more important.

MR. SPEAKER: If there is time we will take up that.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"यह सभा भारत सरकार से अभिप्रस्ताव करती है कि वह बेगुसराय (बिहार) में एक पेट्रो-केमिकल कारखाने की अविलम्ब स्थापना करे।"

अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः सभी जानते हैं कि बेगुसराय में पेट्रो-केमिकल कारखाने की स्थापना के लिए बिहार के जन-प्रतिनिधियों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा बरसों पहले से समय समय पर अभ्यावेदन और ज्ञापन दिये जा चुके हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ने इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की और उसके बाद कुछ देर तक गाड़ी आगे बढ़ी। उस समय की सरकार ने इसमें दिलचस्पी ली लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, तो उसके बाद यह मामला ठप्प पड़ गया।

[श्रीमती कृष्णा साही]

वस्तुस्थिति यह है कि उस समय रचनात्मक कार्य कुछ भी नहीं हुए । यद्यपि उद्योग-धंधों की स्थापना के बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही गई थीं, लेकिन सारे उद्योग-धन्धे ठप्प पड़ गये ।

जिस स्थान पर पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री की स्थापना की चर्चा आज की जा रही है, वहां पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री का सारा इनफ्रा-स्ट्रक्चर मौजूद है । जैसे, वहां पर कम्युनिकेशन्ज, रोड और ब्राड तथा मीटरगेज रेलवे लाइन है । उत्तर भारत की नेशनल हाईवे भी वहीं से पास करती है । बेगुसराय के इलाके में पेट्रो-केमिकल कारखाने की नितान्त जरूरत है । बेगुसराय देश का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है । वहां पर आयल रिफाइनरी और फर्टिलाइजर का कारखाना है और वहीं पर बिहार सरकार का एक थर्मल पावर स्टेशन भी है, जहां से उत्तर बिहार में बिजली की आपूर्ति होती है । गंगा नदी के तट पर बसी इस औद्योगिक नगरी में पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री की स्थापना की नितांत आवश्यकता है । सारा नैफ्था वहां से बाहर चला जाता है । पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री के लिए जितने भी रा मैटिरियल की जरूरत है वह सब वहां उपलब्ध है । आप जानते हैं कि वहीं पर बगल में बरौनी है जो नेक्स्ट डोर है, वहां से कच्चे माल की आपूर्ति की जा सकती है, जैसे कि नैफ्था वहां से मिल सकता है जिस की कि इस उद्योग के लिए बहुत ही जरूरत पड़ती है ।

आप सभी जानते हैं उत्तर बिहार आज देश का सब से घनी आबादी का इलाका है और इस की आबादी हरियाणा प्रान्त की दुगुनी है ।

[SHRI TRIDIB CHAUDHURY *in the chair*]

15.36 hrs.

यह मुख्यत: कृषि प्रधान इलाका है । उस में मात्र एक ही इंडस्ट्री अभी तक मिली है जो कि आप सभी जानते हैं आयल रिफाइनरी बरौनी की है और फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है । ऐसी स्थिति में यदि वहां पर पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री की स्थापना की जाती है तो वह एक सेल्फ-सफिशयेंट इंडस्ट्री हो जाती है और वह वहां एक दूसरे की पूरक हो जाती हैं । उस से हमारे बिहार प्रान्त के विकास में काफी मदद पहुंचेगी ।

उस क्षेत्र में पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री के लिए सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं । कच्चा माल, यातायात और आवागमन के साधन सभी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में यह इंडस्ट्री वहां स्थापित करना काफी एकोनामिकल भी होगा और उत्तर भारत का उस से बहुत एकोनामिक विकास होगा । आर्थिक प्रगति भी हमारी होगी और बहुत अंशों में इस से रीजनल इम्बैलेंस की भी पूर्ति होगी ।

आप जानते हैं कि सांख्यिक सर्वेक्षण के अनुसार तो हमारा सारा बिहार प्रान्त ही दरिद्र-ग्रस्त है और उस में भी यह बेगुसराय सब से पिछड़ा इलाका है । मात्र कृषि पर वह आधारित है और वहां की अधिकांश जनता उसी पर निर्भर करती है जिस के सहारे उस की रोजी रोटी चलती है । मैं यह बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि यदि वहां पर बेगुसराय में पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री की स्थापना हो जाती है तो वहां के लाखों लाख लोगों के लिए वह एक वरदान सिद्ध होगा ।

इसलिए इस प्रस्ताव के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं और पुरजोर मांग करना चाहती हूं कि बेगुसराय में पेट्रो-केमिकल कारखाने की स्थापना की जाये । आप सभी जानते हैं कि बेगुसराय में जो आयल रिफाइनरी है और फर्टिलाइजर का कारखाना है वह कांग्रेस सरकार की देन है, हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की एक देन है और दूसरी वर्तमान प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह सरकार इस दिशा में कारगर कदम उठाएगी ताकि बिहार का पिछड़ापन दूर हो सके ।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved.

"This House calls upon the Government to set up a petro-chemicals unit at Begusarai (Bihar) without any delay."

SHRI KEDAR PANDEY (Bettiah): Mr. Chairman, Sir, I support this Resolution. At Barauni we have got an industrial complex. We have different types of industries. We have got a thermal power station; we have got a fertilizer plant and there is the Barauni refinery also. There are infra-structures for petro-chemical industries. Sir, with this end in view this particular place was developed and we have this industrial complex. I was there in Bihar Government for many years. I know the history of the development of these industries. With this end in view we have started this industrial complex at Barauni. We thought that we shall be able to have a petro-chemical industry. When there was the Congress Government they initiated this scheme. We sent it to the Centre. It was at that stage that this Janata party government came into being. This is the position to day.

As we all know, Bihar State is a major State. It comes just after Uttar Pradesh. It has got a very big population of 60 million people. Then, as far as mineral resources are concerned,

it is a very rich State. There is no doubt about it. In Bihar we have got mineral wealth to the tune of forty per cent of the national mineral wealth. We have got coal, iron and we have also got sufficient water resources. Therefore, this State is basically the richest State, but the paradox is that the people of this State are very very poor. If we take the country as a whole, we have below poverty line 55 per cent population in the rural areas and 50 per cent in the urban areas. In the case of Bihar alone, 76 per cent of its population is below the poverty line. The poverty is at the lowest depth there. As I said, the people are very poor, though the State is very rich basically in all respects. This is the paradox in so far as Bihar is concerned.

It is, therefore, imperative that the Central Government must give a serious thought to this situation. We know that ours is a poor country, but this regional imbalance should be removed. As compared to Bihar, Punjab is rich; as compared to Bihar, Haryana is rich; as Compared to Bihar, Maharashtra is rich. All these States are limbs of India. Bharat, and if Bihar remains poor and it is not developed, how can you think of a prosperous India. If we think of our nation as a whole, in that respect also, it is the national demand that this petro-chemical industry must be set up in Begusarai, very near to Barauni. We must think of it seriously.

The raw material for petro-chemical industry is neptha which is produced abundantly in Barouni refinery and it is but desirable that that raw material must be utilised for petro-chemical industry very near. We have got thermal power station, we have got energy, we have got all these things. The only thing is that we must set up a petro-chemical industry at Begusarai, which is 10—15 miles from Barauni.

SHRI CHANDRAJEET YADAV (Azamgarh): You have an excellent case; you must get it.

SHRI KEDAR PANDEY: The raw material which is produced at Barauni is sent to other places in India for use in petro-chemical industries. Is it not injustice and is it not unwise? After all, Bihar is also a limb of India. What is the transport cost in sending neptha from Barauni to other places? You send neptha to Gujarat, to Mathura and to other places where there are petro-chemical industries. Don't you calculate the cost of transportation? It will be economical if we set up a petro-chemical industry at Begusarai.

Then, what about the unemployment problem in this area? If we set up such an industry at Begusarai, we will be able to provide employment to the unemployed youths of my State, Bihar. That would help in the removal of regional imbalance to some extent. We should consider the possibility of setting up a petro-chemicals industry at Begusarai, from all points of view. The Central Government must take them into consideration. It has been neglected up till now. But now Mrs. Gandhi is the Prime Minister of this country. This is our Government. I am proud to say that this is our Government. This is the Congress Government and we are proud to say like this. So, in this House also we should raise this point. You should also join with me. The whole House should support this demand, so that I may get some strength from you also.

My Minister, Mr. Sethi is here. He should take all these points into consideration.

So far as the Bihar Government is concerned, there is practically no Government there. I do not say this because it is a Janata Party Government. But the Government there is doing nothing. It has got nothing to do with politics. It is a national project. The Government must take this resolution seriously. With these words, I support the resolution whole-heartedly.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH (Banka): I rise to support the resolution put forward by the hon. Member

[Shri Chandra Shekhar Singh]

from Begusarai. The case for the establishment of a petro-chemicals complex at Barauni is one long story of neglect and very indifferent response. The Barauni refinery is the oldest and the largest refinery in the public sector. We sacrificed more than a thousand acres of very fertile land and uprooted hundreds of families, to build up this project, in the hope that a petro-chemicals complex would be developed around the refinery and provide jobs to thousands of young men in the State. We are sorry to say that this project was relegated to a back seat. Petro-chemical complexes have so far been allowed to take shape in other parts of the country, completely over-looking the claims of the Barauni refinery.

I would like to give a little detail of the effort that has been made in this direction by the Government of India and the State Government. Government of India, Ministry of Petroleum and Chemicals constituted a working group for planning and manufacture of petro-chemicals during the 4th Plan, which submitted its report in 1964. The report envisaged (1) the establishment of a naphtha cracker unit to provide the feedstock of basic organic chemicals and intermediates; (2) the utilization of hydro-carbons and gases to produce polymers and plastics, synthetic fibres, detergents, insecticides and pesticides, synthetic rubbers, carbon black etc. and (3) the manufacture of nitrogenous fertilizers from naphtha and associated gases.

Subsequently, a Petro-chemical Project Team was set up by the Government of India for developing Petro-chemicals and allied industries around Barauni Refinery, which submitted its report in April 1966 and suggested setting up of an Aromatic Plant, Capoolactum Plant and such other units. Based on the recommendations of the Report the Government of India gave a token allotment for this project in the Fourth Plan for setting up an Aromatic Plant during the Fourth Plan period. At the suggestion of the Government of India, the State Government drafted the services of M/s. Engineers India Ltd. which is a Government of India Undertaking which made a detailed feasibility report in 1972 for the establishment of petro-chemical complex and down-stream industries at Barauni.

No concrete action was taken at any stage for the implementation of these proposals. It was at one time argued that since part of the crude requirement for refining at Barauni Refinery would be made up by imports for which sources were not fixed, the type of petro-chemical complex which can be developed around Barauni could not be decided. Now with the coming up of the Mathura Refinery, Naphtha can be fed from this source to Kanpur and Gorakhpur. Also now that the full capacity of 3.3 million tonnes of crude per year is being supplied from Assam, the raw material base is firmly decided and the situation calls for decisive action in this respect.

The establishment of petro-chemical complex at Barauni would completely revolutionise the industrial face of Bihar. Naphtha cracker and reformer unit would form the base of synthetic fibre to meet the clothing needs of the people. It would provide raw-material for plastic and rubber for the manufacture of a large number of essential consumer goods. They will pave the way for a network of small scale industries and also help agricultural operations in a big way.

Mr. Chairman, Sir, it is unfortunate that for the last 15 years all the Chief Ministers of the state and all the Industry Ministers of the state have been writing to the Government of India, meeting them, making firm requests to them and having several rounds of discussions with them. But this has led us nowhere. I, as the Industries Minister also tried to push this scheme

up and made the Government of India to agree to this, but so far as we all know, the result has not been very encouraging. The replies were, as usual, clothed in sympathetic language but completely wanting in action. During this period a number of petro-chemicals and downstream industries have been established—I need not give the detailed account—in other parts of the country. But they have remained confined to certain regions in this country and Barauni's claim has been systematically neglected.

I would not like to call it a case of wilful neglect. I do not use any harsh language during this discussion and want to win the sympathy of every corner of this House so that the long neglected demand of Barauni Refinery is sympathically considered and met by the present Government. I have every hope that our distinguished Prime Minister who has taken keen interest in the development programme of our state will certainly look into it and our very able Minister of Petroleum and Chemicals, Mr. Sethi would give it the most sympathic consideration.

I should like to urge upon the Government of India that it should announce a firm time schedule for the establishment of petro-chemical and allied industries at Barauni as soon as possible. With these words I support the motion and commend it for adoption to the House.

श्री जार्ज फर्नानडिस (मुज्फ्फरपुर) : उत्तर बिहार में पैट्रो-कैमिकल कम्प्लैक्स के निर्माण के बारे में पेश इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मैं यह नहीं मानता कि अकेले इस कारखाने से, बिहार अथवा उत्तर बिहार की सभी समस्यायें विशेषकर बेकारी की समस्या का कोई बुनियादी हल निकल सकता है। लेकिन इस प्रकार के कारखाने की आवश्यकता है और एक अर्से से इसकी चर्चा भी रही है लेकिन यह बात अमल में नहीं आई। अगर इस दिशा में कोई ठोस अगला कदम निकट भविष्य में सरकार उठाए तो उत्तर बिहार को कुछ राहत इससे मिल सकती है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

सवाल बुनियादी हो जाता है। इस कम्प्लैक्स के निर्माण के लिए बिजली की आवश्यकता होगी। उसकी क्या स्थिति है। आज बिहार में कुल बिजली निर्माण की क्षमता मेरे ख्याल से लगभग साढ़े सात सौ मैगावाट है और उस में से जो बिजली मिलती है वह ढाई सौ, पौने तीन सौ और बहुत खींचे तो 280–290 मैगावाट समुच्चय बिहार को जिस में जमशेदपुर भी आ गया है, बोकारो भी आ गया, इस्पात के कारखाने भी आ गए, आसपास के बड़े उद्योग भी आ गए, मिलती है। गंगा पार करके आप उत्तर बिहार में जाएंगे तो बरौनी के थर्मल पावर स्टेशन की चर्चा आप करेंगे और वहां जो आज रिफाइनरी है उसकी भी चर्चा आप करेंगे। कुल मिला कर आज उत्तर बिहार में अस्सी मैगावाट से ले कर सौ मैगावाट के बीच में बिजली मिलती है जिस में से अधिकांश बिजली तेल रिफाइनरी और उसके साथ जुड़े हुए खाद कारखानों और उनके साथ जुड़े हुए दूसरे कारखानों को चली जाती है और उत्तर बिहार की आबादी जो तीन करोड़ है, अगर बरौनी के रिफाइनरी कम्प्लैक्स और फर्टिलाइजर कम्प्लैक्स को हटा दें तो मुश्किल से बीस मैगावाट ही बिजली इस तीन करोड़ जनता को मिलती है। मेरे मित्र चन्द्र शेखर जी ने बिहार के विकास के बारे में जो पिछले तीस बत्तीस साल में हुआ है बहुत सुन्दर ढंग से चर्चा की है। उसका इतना सुन्दर विकास इस अर्से में हुआ है कि तीन करोड़ के उत्तर बिहार में मुश्किल से बीस मैगावाट बिजली आज 1980 में जनवरी के महीने में प्राप्त होती है। सवाल बुनियादी है। इस प्रस्ताव का तो मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं और सभी माननीय सदस्यों को करना भी चाहिये। लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कुछ निश्चित निर्णय भी लें इस पर। इस प्रस्ताव के साथ बिजली वाले मामले की बुनियाद में गए बगैर आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। उसको भी उनको खयाल में रखना चाहिये। कल को अगर सरकार यह निर्णय लेती है कि बेगुसराय में या बरौनी में या कहीं भी यह कारखाना स्थापित करना है तो आप लोग बिजली के बारे में क्या करोगे ? तो इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं बुनियादी सवाल को ही छेड़ता हूं कि समूचे उत्तर बिहार के विकास के लिये सरकार कुछ विचार करे। अति उपेक्षित यह इलाका है हिन्दुस्तान का। जैसे आबादी के लिहाज से सब से ज्यादा आबादी उस इलाके में फी स्क्वायर माइल देखने में आती है, उसी तरह से हिन्दुस्तान में उत्तर बिहार से अधिक उपेक्षित इलाका और कोई नहीं मिलेगा। मुजफ्फरपुर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। अगर गंगा पर पुल रहता तो पटना से मुज्फ्फरपुर जाने के लिये घंटा, सवा घंटा का समय लगता। लेकिन आज मुजफ्फरपुर जाने के लिये मोकामह हो कर जाना पड़ता है क्योंकि पुल वहां है। पहले दक्षिण चलिये, फिर उत्तर और फिर पश्चिम चलिये। 20, 25 वर्ष में अरबों रुपये का नुकसान हुआ पुल न होने के कारण, क्योंकि कोई भी चीज उत्तर बिहार को

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

मुकामेह हो कर जायेगी चाहे ट्रक हो, बस हो, मोटरगाड़ी हो या कोई भी यातायात का साधन हो । जो दाम उत्तर बिहार में चीज के देने पड़ते हैं ज्यादा वह अपनी जगह पर और राष्ट्र का जो नुकसान हो रहा है वह भी अपनी जगह पर । और यह जो कमियां हैं इसका वर्णन कहां तक किया जा सकता है ? मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां मीनापुर एक इलाका है उसके विधान सभा क्षेत्र में तुर्की नाम का एक छोटा सा इलाका है जहां एक छोटी सी नदी है जिसकी चौड़ाई 30, 40 गज है । 1944 में उस नदी का पुल टूट गया लेकिन 36 वर्ष में उस पुल को नहीं बनाया गया । उस पुल को बनाने के लिये आज के दामों के चलते 5.4 लाख रुपये चाहिये । लेकिन उसको बनाने की योजना नहीं बन सकी । और अगर वही पुल 10, 15 वर्ष पहले बन गया होता तो मुश्किल से लाख, डेढ़ लाख में बन गया होता । मैं यह जिक्र इसलिये कर रहा हूं क्योंकि यह सारी चर्चा प्रदेश की उपेक्षा के बारे में है । और जिन्होंने प्रस्ताव रखा है वह भी बिहार की उपेक्षा की चर्चा कर रहे हैं और उस दृष्टिकोण से जो अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहे हैं मैं उसका जिक्र यहां कर रहा हूं । यहां पर हम किसी की बात को काटने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक समूचे प्रदेश की उपेक्षा का वर्णन कर रहे हैं इसलिये कि हमारे लिये यह जो प्रस्ताव है काफी अहमियत रखता है । हम यह मान कर चलते हैं कि इसकी आवश्यकता है, और इसकी आवश्यकता न सिफ बरौनी में एक कारखाना बनाने की दृष्टि से है बल्कि समूचे उत्तर बिहार की उपेक्षा को मिटाने और उस परिस्थिति को समाप्त कर के एक अर्स से जो उपेक्षा रही है उसको समाप्त करने का जो हमारा इरादा होना चाहिये उसी भावना से मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं । तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस पर तुरन्त अविलम्ब निर्णय करे ।

16 hrs

एक सवाल किया, जैसे बिजली का मैंने छेड़ा कांटी थर्मल पावर स्टेशन है जिसकी स्वीकृति है, लेकिन उसके लिये पैसा नहीं मिल रहा है, न प्लानिंग कमीशन से और न बिहार सरकार में बैठे हुए लोग यह समझते हैं कि इसको प्रधानता देनी चाहिये । लोगों को प्रधानता के बारे में जो सोच होना चाहिये वह नहीं हो रहा है । किस मसले को किस समय कितनी प्रधानता देनी चाहिए, वह भावना हमें नजर नहीं आती है । कांटी में थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति मिले ढाई बरस हो गये हैं । उसी समय देश के अन्य इलाकों में भी पावर स्टेशनों की स्वीकृति दी गई थी, वे थर्मल पावर स्टेशन हों या अन्य पावर स्टेशन । वहां काम इतना आगे बढ़ गया है कि एक डेढ़ बरस में बिजली मिलने लग जायेगी । पन्द्रह रोज पहले मैं कांटी में था । वहां दीवार खड़ी करने के लिए ईंटें लगाने का काम शुरू हुआ है---पावर हाउस की दीवार नहीं, बल्कि उसके लिए ली गई जमीन के लिए बाउंडरी की दीवार का काम शुरू हुआ है ।

उस पावर स्टेशन का काम जिस रफ्तार से होना चाहिए, अगर उस रफ्तार से किया गया होता, तो अगले साल, या इस साल के अन्त तक, वहां से 110 या 220 मेगावाट बिजली मिलने लग जाती ।

हमने सरकार के भीतर रह कर भी अनुभव किया, उससे पहले भी अनुभव किया और आज भी अनुभव कर रहे हैं कि जब भी इस प्रकार की चर्चा होती है तो प्रश्न किया जाता है कि पैसा कहां से लाया जाये, क्योंकि विकास पैसे से जुड़ा हुआ है । मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र पेट्रोलियम मिनिस्टर मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे ....(**व्यवधान**) क्या माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है ? वह बार-बार चिल्ला रहे हैं । हम किसी भी सवाल का जवाब देने की काबलियत रखते हैं । हम बहुत सालों से इस सदन को देख रहे हैं । वह इतने परेशान न हों । (**व्यवधान**) माननीय सदस्य रीयलाइजेशन की बात कर रहे हैं । उन्हें तो रीयलाइजेशन सात दिन पहले हुआ है, मगर हमें बहुत पहले हो गया था ।

मैं मंत्री महोदय के माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं । दिल्ली में होने वाली एशियन गेम्ज पर 40 करोड़ रुपया खर्च होना है । अगर वह 40 करोड़ रुपया और उसमें लाने वाली सीमेंट और इस्पात आदि सारी सामग्री उत्तर बिहार के इस थर्मल पावर स्टेशन और पेट्रो-केमिकल कम्प्लेक्स पर लगाने का फैसला हो जाता है, तो फिर पैसे का सवाल उठाने की जरूरत नहीं होगी । यह प्रधानता का झगड़ा है कि क्या 40 करोड़ रुपये और उस रुपये से खरीदी जाने वाली सीमेंट, इस्पात और अन्य सारी सामग्री का इस्तेमाल दिल्ली में एशियाई खेल-कूद के लिए खर्च किया जायेगा या उत्तर बिहार में लगाया जायेगा, जहां की 80 फीसदी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है, जहां की बकारी हिन्दुस्तान में और किसी भी प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी---उससे अधिक है । यह एक बुनियादी सवाल है । (**व्यवधान**) हमें इन बातों का ख्याल है इसी लिए हमारी सरकार ने फैसला किया था कि एशियाई खेल-कूद दिल्ली में नहीं होंगे और यह पैसा गांवों के विकास पर खर्च किया जायेगा । हमारी सरकार ने यह फैसला किया था और उस फैसले को बदलने का काम आपने शुरू किया है ।

मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि एक तो वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और इसके साथ ही वह बिजली घर वाले मामले को भी जोड़ दें । जैसा कि मेरे मित्र, श्री पांडे ने कहा है, इसके लिए टाइम तय कर लिया जाये । यह नहीं कहना चाहिए कि यह भी होगा वह भी होगा सब कुछ होगा । वह तो हम ने तीस बरसों में बहुत देख लिया है । आपने हमारे तीस महीने देखे हैं, हमने आपके तीस साल देखे हैं ।

. . . . (व्यवधान) . . . .

क्यों परेशान होते हैं ? जनता ने हम को भी देखा है और आप को भी देखा है । उस की चर्चा बहुत कर सकते हैं, बहुत समय है । इतना घबड़ाइये मत । आप को भी समय है, मुझे भी है । क्यों परेशान हैं ?

इसलिए इसके लिए एक कान्क्रीट, टाइम फ्रेम मंत्री महोदय तय कर लें और रुपये पैसे की अगर दिक्कत है तो एशियाई खेल कूद में डालने वाला रुपया उसमें से हटा कर तत्काल इस काम्प्लेक्स को बनाने के लिए और उसके लिए आवश्यक बिजलीघर बनाने के लिए डालने का काम करें । समूचे उत्तर बिहार के विकास को मद्दे-नजर रख कर एक ऐसी योजना वह बनाएं और बिजली मिलने तक, पैट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स खड़ा होने तक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और लोगों को तत्काल राहत देने वाले जो उद्योग बना सकते हैं उन को बनाने के लिए अपनी सरकार के माध्यम से तत्काल योजना बना कर आगे बढ़ें और हम ने जो योजना बना कर रखी थी उस को अमल में लाने का काम करें ।

श्री आर० एल० पी० वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं श्रीमती कृष्णा साही द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । आप जानते हैं, बहुत से मित्रों ने पहले चर्चा की है, बिहार औद्योगिक दृष्टिकोण से भारत के नक्शे में बीसवें स्थान पर है जब कि दक्षिण बिहार में कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, बौक्साइट आदि खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं और सारे भारत के लिए वह एक गौरव की चीज है । उत्तर बिहार जहां कि खेती के लिए उर्वरा जमीन है उस क्षेत्र में तीन करोड़ से अधिक की आबादी है । वहां पढ़े लिखे नौजवान हजारों और लाखों की संख्या में बेकारी से ग्रस्त ह । इस दिशा में पिछले पन्द्रह वर्षों से यह प्रयास चलता रहा है कि एक पैट्रो-केमिकल इंडस्ट्री वहां लगायी जाय ताकि वहां के लोगों का भी नियोजन हो और उन की आर्थिक स्थिति सुधरे । पैट्रो-केमिकल वहां बनाने के लिए सारे साधनों की मौजूदगी के बावजूद यह सरकार सौतेला व्यवहार उस के साथ कर रही है । इस दिशा में बिहार के हमारे भूतपूर्व उद्योग मंत्री श्री चन्द्र शखर सिंह ने और बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री पांडेय जी ने भी अपनी गाथाएं रखी हैं, अपने अनुभव की बातें रखी हैं । साथ साथ भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्री जार्ज साहब भी मौजूद हैं । 1978 में बिहार के उद्योग मंत्री श्री ठाकुर प्रसाद के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल यहां बिहार भवन में आया । उन लोगों ने भी इस प्रस्ताव को मनवाने के लिए हम लोगों से निवेदन किया था और हम लोगों ने सामूहिक रुप से जार्ज साहब को कहा था कि इस की मंजूरी दी जाय । लेकिन यह भी राजनतिक उथलपुथल के अंदर उलझ रहे और अब फिर ऐसा अवसर आया है जब कि यहां एक प्रस्ताव के रुप में यह चीज आई है । मैं चाहूंगा कि इस उद्योग के लिए निश्चित रुप से भारत सरकार को स्वीकृति देनी चाहिए ताकि उत्तर बिहार में जहां कोई इंडस्ट्री नहीं है एक काम्प्लेक्स बन सके । यहां पर बरौनी का खाद का कारखाना और आयल रिफाइनरी है, अन्य साधन भी पट्रो-केमिकल इंडस्ट्री के लिए यहां मौजूद ह, सारी सुविधाएं हैं । हमारे भूतपूर्व उद्योग मंत्री जार्ज साहब ने जो बिजली की कमी के बारे में बताया है, ऐसे पहलुओं को लेकर भारत सरकार इसे और टालने का प्रयास न करे । इस के लिए सभी संसद सदस्य जो बिहार के हैं और जो बिहार के बाहर के भी हैं, उन को सबको इस क्षेत्र के विकास के लिए इसे समर्थन देना चाहिए । मैं हरियाणा और पंजाब के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वहां पर न लोहा है, न कोयला है, न तांबा है फिर भी सारी इण्डस्ट्रीज वहां पर लगी हुई हैं जबकि बिहार में सारे साधन मौजूद हैं, सारा कच्चा माल है, सारे खनिज पदार्थ हैं उसके बावजूद बिहार की उपेक्षा की जा रही है । इसीलिए आज भारत में बिहार राज्य बीसवें स्थान पर है । ऐसी स्थिति में भारत सरकार को बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए । पहले भी कांग्रेस सरकार ने इसको मंजूर किया था और आज भी कांग्रेस सरकार पूरी सक्षम है इसलिए मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार वहां पर पैट्रो-केमिकल इण्डस्ट्री को पूरा सहयोग दे ताकि उस क्षेत्र का पूरा विकास हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, अभी हम लोग बरौनी पैट्रो-रसायन उद्योग के सम्बन्ध में यहां चर्चा चला रहे हैं । उस प्रदेश का मैं भी हूं और हम लोगों ने विगत सत्र में भी बिहार का कैसे विकास हो, इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था । आज भी शाही जी के रेजोल्यूशन को प्रायर्टी मिल गई है जिससे सरकार का ध्यान पुन: आकृष्ट करने का मौका हमें मिला है । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करुंगा कि किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, अभी यहां पर जितने माननीय सदस्य बोले हैं, सभी ने इस बात को स्वीकारा है और इमानदारी पूर्वक यदि आप देखेंगे तो बिहार का स्थान तो पिछड़ा है ही, बिहार में भी जो उत्तरी बिहार है, खासकर जो गंगा के उस पार का इलाका है, उसकी हालत इतनी दयनीय है कि यदि यहां की कोई टीम वहां पर जाए तभी इस बात का पता चल सकता है । आज हमारे यहां बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, फर्टि-लाइजर कारखाना भी है लेकिन उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है । वहां पर जो गरीबी और भुखमरी है उसको जब हम उठाते हैं तो बहुत से साथी पक्ष और विपक्ष की बात बोलते हैं, कोई कहता है कि आपकी

[श्री राम विलास पासवान]

सरकार थी तो आपने क्या किया, हमारी सरकार है तो हमने क्या किया ? मैं कहना चाहता हूं अपने नये साथियों से कि पार्लियामेन्ट में हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि एक दूसरे की नुकताचीनी करें । जिस समय हम लोग ट्रेजरी बेंचेज में थे उस समय भी हम लोग मैक्सिमम प्रयास करते थे कि जिस प्रान्त से, जिस क्षेत्र से जो सदस्य यहां पर चुनकर आया है वह, यहां पर हमें पार्लियामेंट के प्रोसीजर और डायरेक्शन की किताब मिली हुई है उसका अध्ययन करके, अधिक से अधिक समस्याओं को सरकार के सामने रखे । (व्यवधान) मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आपको सुनना तो पड़ेगा ही । और अगर एक साल तक यही बात रही तो आप लोग देश में कहीं भी घूमने लायक नहीं रहेंगे । . . (व्यवधान) . .

सभापति महोदय, मैं जब फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, कालिज में नाम लिखाया था, तो मैं समझता था कि कालिज मेरी जेब में है । लेकिन जब मैं सैक्ण्ड ईयर और थर्ड ईयर में गया, तब मुझे पता लगा कि मैं वहां का एक आर्डिनरी विद्यार्थी हूं । इस लिये जो लोग संसद में आये हैं, वे यह समझ ले कि दसंस उन की पाकिट में नहीं है . . . . (व्यवधान) . . . . मैं यह बात कहना चाहता हू—चाहे कोई विपक्ष की बात हो या पक्ष की बात हो, जो भी सामाजिक कल्याण की बात हो जो किसी भी प्रदेश को उठाने की बात हो, देश को आगे बढ़ाने की बात हो, उस में न हम को 30 साल की बात रखनी चाहिये और न आप को तीन साल की बात रखनी चाहिये । आप को यह सोचना चाहिये कि उस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है । हमारे जो अनुभवी साथी हैं, उन्होंने बिहार के सम्बन्ध में कहा है कि किस तरह से उस का विकास किया जा सकता है । मैं भी आप के सामने यह बात कहना चाहता हूं कि जब भी उन समस्याओं के निदान के बारे में डिबेट होगी, मैं भी उस में बोलूंगा और आप को बतलाऊंगा कि उस क्षेत्र के विकास के लिये काटेज इण्डस्ट्रीज का कितना महत्व है । जार्ज साहब ने भी अभी बतलाया कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का क्या महत्व है । जब देश के परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे, जब देश की गरीबी को दूर करने का संकल्प लेंगे, जब देश की बेरोजगारी को दूर करने का संकल्प लेंगे, जब देश के नौजवानों को काम देने का संकल्प लेंगे तो आप सब को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं । आप को लघु उद्योगों पर आधारित होना पड़ेगा । यह एक अलग विषय है, लेकिन इस समय तो हमारे सामने जो प्रस्ताव है, उस पर हम को विचार करना चाहिये । बिहार में इस पैट्रो-कैमिकल उद्योग लगाने के सम्बन्ध में कहा गया है कि वहां पर हर चीज उपलब्ध है । कच्चा माल बहुत मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्जा उपलब्ध है—इन सब उपलब्धियों को देखते हुए यदि यह कारखाना वहां लगा दिया जाये तो इस से दूसरी जगहों के मुकाबले बहुत कम खर्चा होगा । बिहार की अन-एम्पलायमेन्ट की समस्या दूर होगी और न केवल राज्य को बल्कि केन्द्र को भी लाभ होगा ।

इस के साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस बात को भी देखें कि जब भी बिहार में कोई कारखाना लगे उस में वहां की जो स्थानीय जनता है, जो गरीब लोग हैं, हरिजन हैं, नौकरियों में उन को प्राथमिकता दी जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि बिना किसी नुक्ताचीनी के, बिना किसी विलम्ब के इस को सरकार मान ले ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । श्री पांडे जी को याद होगा, चुनाव जीतने के बाद मैंने कहा था कि लोक सभा में उत्तर बिहार और पूरे बिहार के प्रश्न पर राजनीतिक मतभेद नहीं रहना चाहिये, बल्कि सब को मिल कर केन्द्रीय सरकार पर उस के विकास के लिये जोर लगाना चाहिये, ताकि बिहार का उत्थान हो सके ।

मैंने श्री चन्द्र शेखर सिंह जी और जार्ज साहब का भाषण बहुत ध्यान से सुना । मुझे इस बात पर कुछ हंसी भी आई जब श्रीमती साही जी ने कहा कि कांग्रेस राज्य में फर्टिलाइजर प्लांट बना, कांग्रेसी राज्य में बरौनी का थर्मल पावर प्लांट बना । इन सब बातों के लिये आप प्रंशसा लें, इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता, लेकिन जहां तक बेगुसराय में इस पैट्रो-कैमिकल काम्प्लेक्स के लगाये जाने की बात है, उस इलाके में वर्षों से यह अभियान चल रहा है । हमें याद है.—जब 1977 के पहले मैं लोक सभा का सदस्य था, हमारे श्री योगेन्द्र शर्मा, एम० पी० तथा कुछ दूसरे लोग इस मांग को ले कर बेगुसराय से आये थे और मंत्री महोदय से मिल कर उन्होंने इस मांग को उन के सामने रखा था ।

जहां तक श्रीमती साही जी ने इस समस्या पर जोर डाला है—यह उन्होंने सही काम किया है । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं—1977 के पहले जब इस सदन में कांग्रेस का बहुमत था, इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं, उस समय एक प्रस्ताव आया था जिस में कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार पिछड़े हुए इलाकों के लिये एक योजना बनाये, जिस में उन के विकास के लिये औद्योगिक कार्यवाहियां की जायें और उस कार्य में उद्योगपतियों और सरकार को भी योगदान करना था । मैं इस मौके पर इतना और कहना चाहता हूं—बेगुसराय तो पिछड़ा इलाका है ही, लेकिन वहां एक और बहुत बड़ा पिछड़ा इलाका है—जिस का नाम "चम्पा

है, जिस के लिये गांधी जी ने सत्याग्रह किया था । पाण्डेय जी जानते हैं कि चम्पारन में शुगर उद्योग के सिवाय और कोई उद्योग नहीं है । वहां पर उद्योगों के साधन भी मौजूद हैं। चम्पारन में कागज का उद्योग भी चालू किया जा सकता है । मोतिहारी में एक रमाकास्ट इंजनियरी कम्पनी खुली हुई है । उसमें गवर्नमेंट के करोड़ों रुपये लगे हुए हैं लेकिन वह आज तक बंद है । उसको खोलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जिससे लोगों को काम मिल सके ।

इसी तरह से उत्तर बिहार में और भी उद्योग खोले जा सकते हैं । जैसा कि शाही जी ने कहा वहां पर तमाम साधन मौजूद हैं, पैट्रो-कैमिकल काम्प्लेक्स खोल सकते हैं । मैं कहता हूं कि उत्तर बिहार में बहुत सारे इलाकों में ऐसे साधन मौजूद हैं जिन से वहां बहुत से उद्योग खोले जा सकते हैं । कागज बनाने का कारखाना वहां खोल सकते हैं, चकिया में जूट मिल खोल सकते हैं । इसी प्रकार के और भी कारखाने खोल सकते हैं ।

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI P. C. SETHI): I am sorry to interrupt the hon. Member. We are discussing only a particular point; dont bring in other karkhanas.

श्री कमला मिश्र मधुकर : आप जानते हैं कि आपकी तरफ से बोलने वाले लोगों ने भी अपने आपको सीमित नहीं रखा है । इसीलिए इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार उत्तर बिहार की गरीबी और बेकारी की समस्याओं के बारे में सोचे और अपने पूर्ण निर्णयों को अमल में लाए । उत्तर बिहार में, बरौनी में पैट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स खुला हुआ है । लेकिन उत्तर बिहार में और भी कच्चा माल मौजूद है, सिर्फ सरकार को वहां पर कदम उठाने की जरुरत है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि सरकार ऐसी कार्यवाही भी करे जिससे उत्तर बिहार में, जहां-जहां साधन मौजूद हैं, उनका सही-सही इस्तेमाल हो सके और उत्तर बिहार की बेकारी और गरीबी की समस्या को दूर करने में हम आगे बढ सकें।

श्री इमर लाल बैठा (अररिया) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आज बहुत देर से ही सही, मगर एक सही प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है और उसका क्या महत्व है, उस पर अभी काफी प्रकाश डाला गया है ।

यों तो हम सभी को मालूम है कि बिहार औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । उसकी आर्थिक स्थिति का भी यहां जिक्र किया गया । उसके बारे में सभापति महोदय ने सुना होगा कि बिहार के लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे की स्थिति में बने हुए हैं । इसलिए एकमात्र रास्ता राज्य की दशा सुधारने का रह जाता है कि वहां का उद्योगीकरण किया जाए । वहां पर खास कर ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाए और अविलम्ब की जाए जिनकी कि वहां संभावनाएं हैं ।

बरौनी, जहां पर कि पेट्रो-काम्प्लेक्स की स्थापना का प्रस्ताव है, सभापति महोदय को मालूम होगा कि वह स्थान बहुत दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । जैसा कि अभी कहा गया, वह स्थान तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला स्थान है । दक्षिण बिहार में जहां कुछ उद्योगों की स्थापना हुई, उनसे बहुत ही कम, या यह कहना चाहिए कि यह पहला कदम है कि उत्तर बिहार के दरवाजे पर, बरौनी में इस उद्योग की स्थापना हुई । अगर यह पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स की वहां पर शुरुआत की जाती है तो बिहार में इससे अन्य छोटे-छोटे उद्योग भी पनपेंगे और लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी ।

दक्षिण बिहार से कोयला या अन्य जो सामान है जिस की कारखानों में आवश्यकता होगी, उसकी आपूर्ति होगी । रेल हैड होने की वजह से वहां बना हुआ सामान बाहर भेजने में मदद मिलेगी, उस में भी कोई कठिनाई नहीं होगी । इसके साथ-साथ वहां जो नेपथा है जिस का उपयोग हम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, पैट्रोल केमिकल कम्प्लैक्स की स्थापना हो जाने से उसका भी उपयोग हो सकेगा । इसके साथ-साथ बरौनी रिफाइनरी से जो वाई प्रोडक्ट्स पैदा होती है उनका भी हम उपयोग कर सकेंगे । इससे उत्तर बिहार में कृषि के विकास की जो बहुत आवश्यकता है उसकी सम्भावना का भी विस्तार होगा ।

श्री जार्ज फर्नांडीस ने कहा है कि ऊर्जा की बहुत कमी है । मैं कहना चाहता हूं कि केवल बिजली की नहीं बल्कि कोयले, डीजल, पैट्रोल आदि की भी कमी है । अगर हम को इन कारखानों का विकास करना है तो इस ऊर्जा की कमी को दूर करने के उपाय भी हम को निकालने होंगे । आज कोयले का उत्पादन कम हो रहा है । इसकी वजह से यातायात में कठिनाई हो रही है । कोय को ढोने के लिए वैगंज की कमी भी बताई जाती है । बरौनी रिफाइनरी में या जहां बिजली उत्पादन के कारखाने हैं उन में अगर पूछा जाता है तो बताया जाता है कि हमारे पास कोयला ढुल कर नहीं आ रहा है और इस कारण से हम बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं । और भी बहुत सी दिक्कतें हैं जिन को योजनाबद्ध तरीके से आपको दूर करने की कोशिश करनी होगी और उनका हल निकालना होगा । मुझे अभी मालूमम

[श्री डूमर लाल बैठा]

हुआ है कि बहुत पहले से बिहार सरकार की ओर से कई बार इन बातों को आपके सामने रखा गया है और यहां पर भी इसके बारे में कोशिश की गई है कि इस उद्योग को बहुत पहले से ही वहां स्थापित कर दिया जाता लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देर से ही सही इस उद्योग को अविलम्ब आपको वहां स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिये और जो कठिनाइयां हैं, अगर सरकार का इरादा पक्का हो तो उनका हल निकाल कर उन पर भी विजय पाई जा सकती है और इस उद्योग की स्थापना में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

मुझे खुशी है कि इस सवाल पर किसी भी माननीय सदस्य को कोई एतराज नहीं है और न ही होना चाहिये। बिहार में इस प्रकार के उद्योग के लिए बरौनी से उपयुक्त स्थान है। वहां पर असम से तेल आता है, वहां पर तेल शोधक कारखाना भी है। उससे जो बाई प्रोडक्ट्स पैदा होती है उनका भी वहीं पर उपयोग हो सकता है, उन पर आधारित उद्योग भी वहां पर स्थापित हो सकता हैं।

सदन की भावनाओं का ख्याल करते हुए मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाएगी। यही मेरी मांग है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : श्रीमती कृष्णा साही द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय की सेवा में दो एक निवेदन करना चाहता हूं। पहला यह है कि सातवीं लोक सभा में यह पहला गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुआ है। भारत की जनता ने और उस में बिहार की जनता ने भी इस सरकार को केन्द्र में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है, अग्रणी वह भी रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। बिहार की जनता टिकटिकी लगाए आपकी ओर देख रही है। बिहार की जनता एक बार धोखा खा चुकी है। जार्ज साहब ने उत्तरी बिहार की चर्चा की है। वहां पर व्याप्त गरीबी की, वहां पर आवागमन के साधनों के अभाव की चर्चा की है। वह क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है इसको उन्होंने आपको अच्छी तरह से बताया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं उसी उत्तरी बिहार की धरती पर पैदा हुआ हूं, वहीं पर पला हूं। अगर उनको कष्ट होता है कभी कभी समय मिलने पर वहां जाने में तो हम लोगों को जो वहीं पैदा हुए हैं कितना कष्ट होता होगा इसका आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने ठीक ही कहा है कि पट्रो कैमिकल के स्थापित हो जाने से और भी उद्योगों की स्थापना में योगदान मिल सकता है, उनकी स्थापना के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित हो सकती है। मैं बतलाना चाहता हूं कि कांटी में, मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना का इन्होंने निर्णय लिया था लेकिन मुझे खेद है कि जार्ज साहब ने अपने कार्यकाल में कोई कालबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया और उस की वहां स्थापना नहीं की। अगर तत्परता से काम लेते तो निश्चित रूप से उत्तर बिहार को 120 मेगावाट बिजली मिलती। लेकिन आपने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। परन्तु अब मुझे विश्वास है कि उत्तर बिहार के पिछड़ेपन को मंत्री जी ध्यान में रखेंगे। माननीय सेठी जी ने श्री कमल मिश्र मधुकर को इंटरप्ट किया, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर बिहार में चीनी उद्योग के अलावा और कोई उद्योग नहीं है जिससे नौजवानों और काश्तकारों को रोजगार मिले। और कोई कैश क्रोप नहीं है। इसलिये इसको नजरंदाज नहीं किया जाय और मंत्री जी ध्यान में रखें। समय पर गन्ने का मूल्य न मिलने से जो चीनी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है और इस वर्ष जो गन्ने के उत्पादन में कमी आ रही है उसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा चीनी उद्योग पर। इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि सातवीं लोक सभा का यह पहला संकल्प है जो श्रीमती कृष्णा साही द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसको प्रधानता दीजिये और कोई कालबद्ध प्रोग्राम बनाइये, ताकि एक, दो साल के अन्दर यह कारखाना स्थापित हो और बिहार में बरौनी में लोगों को रोजी रोजगार मिले और लोगों को विकास करने का अवसर मिले।

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI P. C. SETHI): Sir, I am highly grateful to the hon. Members who have participated in the discussion of this Resolution and have unanimously thrown out very useful suggestions—starting from Shrimati Krishna Sahi, followed by Shri Kedar Pandey, Shri Chandra Shekhar Singh, Shri George Fernandes, Shri R. L. P. Verma, Shri Ram Vilas Paswan, Shri Komla Mishra Madhukar, Shri Dumar Lal Baitha and Shri Krishan Pratap Singh.

The State of Bihar is inhabited by poorer people, although the State as such, the land of Bihar, is not poor, is rich. It is a contradiction and an irony of fate that, in spite of the fact that Bihar is rich, and nature has endowed it with all possible things, Bihar continues to remain a poorer

State from the point of view of people.

As far as the question of development of Bihar as such, and particular-'uttar' Bihar which the hon. Members have mentioned here, is concerned, the question of petro-chemicals would not have arisen if the Barauni Refinery had not been established. Therefore, the House would kindly appreciate that the intention of the Central Government to develop this area was there. The Barauni Refinery has been established not on the basis that crude is available in Barauni. Normally it is said that industry should be established where the raw material for that is available. Thermal power station should be located where coal is available. It is rather difficult to carry coal in order to run thermal power plants. It is economical, it is better, if thermal power stations are located in such areas where the raw material like coal is available. That also solves the problem of transportation and transport bottlenecks. Therefore, this is an admitted fact and Government should generally go by this that wherever the raw material on which a particular industry can be based is available, the industry should be estiblished there. From this point of view I would only like to make one point clear, that the debate was very nice, members were quite suggestive and they have put forward their case very strongly. I am only sorry for one thing—for the heat which was generated by Mr. Paswan who is quite young, energetic—he appears to me like that. But unfortunately he seems to be stepping into the shoes of Mr. Kachchwai and unnecessarily, where heat is not necessary, he generated the heat saying that nobody will be allowed to speak after a year. That was not the object. We are all here, we allow each other to speak and understand each other and understand the problems and then find a solution particularly in such cases where there is unanimity.....

श्री राम विलास पासवान : मैं ने वह नहीं कहा था ।

SHRI P. C. SETHI: In a way I am elderly to you and although I belong to the other party, I have every authority to give you an advice as a friend.

As far as this Barauni refinery is concerned, this refinery was established there only to develop that area. Although originally pipeline was laid there from Haldia and this refinery was based on the basis of the imported crude, but, fortunately, for us this pipeline which comes from Haldia to Barauni is of a smaller capacity and it could not have increased the capacity of the Barauni refinery. But fortunately, for Bihar and for us, particularly for a country like India which needs petroleum products so badly, it was good that we could pump in more crude from Assam to the Barauni refinery and increase its capacity. Had it not been established there, the question of petro-chemical complex could not have arisen at all. Therefore, the intention of the previous government was very clear—that we are interested and we shall continue to remain interested in the development of all backward areas, particularly, where very large sections of society are living and where nature has given us abundant resources to develop that area. The only constraint could be financial constraint. But then it could be phased over. It is true that in a country like India everything cannot be done in a very short period of time. The only constraints could be financial.

As far as this aspect is concerned, I fully respect the feelings of the hon. Members who have expressed strong feelings. This petrochemical complex would naturally be based on the outcome or whatever is the produce of the Barauni refinery.

I would in brief like to give the history so that you can appreciate the matter. As far as this question is

[Shri P. C. Sethi]

concerned, a Working Group was constituted by the Government of India to go into this matter and this Working Group was appointed in September 1977 for the first time to go into the complex problem of finding out what could be done in regard to the petrochemical complex. But, unfortunately, the Government was indecisive. They could not force the issue in a time-bound programme for which the hon. Members now ask this government to have a time-bound programme, with the result that this Working Group which was originally constituted in September 1977 was reconstituted in May 1978. Therefore, all these 8 or 10 months were lost unnecessarily only because the then Government perhaps was interested in this person or that person coming into that Working Group.

Therefore, unnecessarily, this time was lost. Anyhow, this Working Group Report has gone into various factors. I would not like to waste the time of this House. At this moment, I would only say that the Working Group report was submitted to the Government on 28th of February 1979. Thereafter this was considered in the ministry and by the Secretaries at the meeting convened by the Member (Industry), Planning Commission and a decision was taken at the official level and the same is being processed for obtaining various approvals.

As far as the location is concerned, it goes without saying that Barauni is bound to have a Petro-Chemical Complex based on Barauni products. The only question is about the location of the complex. Unfortunately, the previous Government too could not decide about its location. I do not know why they were delaying it. Maybe. they were not very sure as to what was to be done. Our Government is hardly seven or eight days old. But we have taken an immediate decision to appoint an expert committee which will go into the question of location. This will be based not on political considerations, not even on considerations of favouritism to this area or that area, to this constituency or that constituency. Normally those members who are ministers wield more influence, better influence than others and they try to take away something to their constituencies which normally should have gone to some where else. We are constituting this Committee purely on technical basis which will consist of such people who will go into the question of location only from the point of view of merits. I can only assure the hon. Members that I have heard them with rapt attention and I have noted down the points which they have made. They have made out a strong case for this. I would give them a full opportunity for expressing themselves. Not only that They can also prepare the data or memorandum on a scientific basis pleading the causes for the particular location which is being mentioned in this Resolution. After the Committee is set up, we will give full opportunity to the hon. Members coming from Bihar whether from this side or from that side—we will give them three days or seven days—we would not mind it, we would give a full opportunity to hon. Members coming from this region to express themselves before this Committee so that they can take into account their viewpoints, technical and other favourable points, mentioned in favour of this particular proposal.

Even after constituting this committee, I would like to assure the hon. Members that we will give this Committee a time-bound programme. This would not be like a Committee where dates are generally extended because the Committee is not able to fulfill that. Various Committees and Commissions are appointed but they are never able to complete the work and always the dates of such committees and commissions are extended. It

is said generally that if you want to avoid a particular thing or to delay it, then appoint a Committee. It is not our intention to appoint a Committee for that purpose. From that point of view we would not want to delay it. It will be a Committee which would hasten the entire programme. We do not want to waste the products that would come out of the Barauni Refinery. We want to utilise them in the best possible way for the benefit of the country, our countrymen.

Mr. George Fernandes has said something about the Asian Games. If they would have taken up the work during their regime, it would have cost us Rs. 22 crores. Now it is going to cost us Rs. 32 crores. It would not be the pride of a nation before the international comity of nations if you say that the Asian Games would not be held in India.

As a matter of fact, this was a cabinet decision. Even your previous Government's decision was that the Asian Games would be held here. But, unfortunately, Chaudhury Saheb had his own say which was over and above the Cabinet decision. According to my information the Cabinet decision was never revoked. But he himself on his own started saying in public speeches that he was not in favour of holding any Asian Games here. Why should he say so when it is a Cabinet decision. Now, on account of the cost escalation, we are going to spend Rs. 32 crores instead of Rs. 22 crores. The Asian Games would definitely enhance the prestige of Indians and this country throughout in the comity of nations. And, therefore, we are proud that we have taken a correct decision and we have undone what was very unfair and which was bad for the name of our country. I am particularly mentioning this point that Asian games.....

श्री बनिक लाल मंडल (झंझारपूर) : बिना खाये और पानी पिये लोग मर जाते हैं, यह शेम नहीं है ?

श्री पी० सी० सेठी : आपके समय में तो यह रहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा और देश के प्रधान मंत्री बने तो सारे देश में सूखा पड़ गया । इसलिए कितने लोग मरे और कितने लोगों ने माइग्रेट किया, उसको आप छोड़ दीजिए ।

As far as petro-chemical complex is concerned, it is not a question of ten or twenty crores. It is a question of 500, 800 or 1200 crores. By and large as things will grow and if Barauni refinery's capacity is further enhanced then petro-chemical complex cost would not be less than Rs. 100 to 200 crores. It is going to be a big affair. By stopping the Asian grames and sparing Rs. 32 crores you will not even have the foundation of a petro-chemical complex.

Further, Sir, I would also like to say that petro-chemical complex is not a thing which would only enrich a particular area where it is going to be located. A complex itself means that it is going to be a number and variety of factories, number and variety of products coming out of this refinery. Therefore, Sir, it is bound to be that it will spread out. It will not only help a particular place but it will help the round-about area in a big way and out of these institutions which would come cut of the petro-chemical complex many other subordinate industries and allied industries based on them would also crop up and come up.

Sir, I fully appreciate the sentiments of the hon'ble Members. I can only assure them that we have no prejudice. Unfortunately, it appears that there is a fear complex and there is a doubt that we would not favour this area. There is no question of favour or fear. According to me this area—in view of the fact that Barauni refinery is there I am saying only from layman's point of view. I am not a technical person that round-about Barauni where Barauni refinery is there a petro-chemical complex is bound to come. Whether it is five

[Shri P. C. Sethi]

miles this side or five miles that side is immaterial. Therefore, I would beg of the hon'ble Members that we fully appreciate their sentiments. We fully appreciate their points of view. We have appreciated the arguments advanced in their favour. They will be given full opportunity to express themselves before this Group and I again assure this House that it will be a time-bound programme. We will try to take up this programme in most earnestness. Therefore, I would request the hon'ble mover of this Resolution and other hon'ble Members that in order to avoid controversies they may not press it. Once you name a place then there are so many controversies. We have seen what had happened when there was one Chair and three contestants. If there is one Chair and one person then there is no problem. Therefore, if you pass a resolution like this naming a particular place without support of the technical data that would create problems rather than solve them. Unnecessarily people found-about. will say we also have got a claim.

Therefore, in order to avoid heat, in order to avoid controvercy, and in order to have a just and a technically-based decision, I would request her to withdraw the Resolution. I would urge upon her that in her own interest and in order to avoid embarrassment to the Government she may kindly withdraw the Resolution and cooperate with us. Thank you.

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री पेट्रोलियम तथा रसायन को धन्यवाद देना चाहती हूं और बधाई भी देती हूं कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि टैक्नीकल एक्सपर्टस की एक कमेटी बनाई जायगी, जो इस मामले को देखेगी कि पैट्रोलियम कैमिकल काम्प्लेक्स की स्थापना किस प्रकार से हो :....

श्री पी० सी० सेठी : किस प्रकार हो और कहां हो।

श्रीमती कृष्णा साही : मुझे इस बात से भी बहुत खुशी हुई कि यह कमेटी एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के अन्दर होगी। लेकिन मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहती हूं। यह बात सही है कि पैट्रोलियम कैमकिल इण्डस्ट्रीयल काम्प्लेक्स की स्थापना के उद्देश्य से ही बरौनी में रिफाइनरी का प्रारम्भ कांग्रेस आई के शासन काल में हुआ था। बरौनी रिफाइनरी और फर्टिलाइजर के बीच में इतनी सारी जमीन है जिस में पैट्रोलियम केमिकल काम्प्लेक्स की स्थापना हो सकती है।

मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देती हूं और अपने प्रस्ताव को वापस लेती हूं।

श्री धनिक लाल मंडल : यह सदन की प्रापर्टी है, ऐसा सदन की राय से ही हो सकता है।

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH (Banka): If the Minister has objection to this Resolution only because a particular place is named, with your permission, I move:

> "*For* the words 'Begusarai (Bihar)' *substitute* 'around the Barauni oil refinery.'

This is what I would like to be substituted.

MR. CHAIRMAN: Order please. You have to move an amendment. There is a procedure. Let us follow the procedure. Now, the point is this: Since Shrimati Sahi wants to withdraw her Resolution, I have to put it to the House. That is the procedure. I am now putting it to the House.

Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shrimati Sahi be withdrawn?

SOME HON. MEMBERS: No.

MR. CHAIRMAN: I am putting it to the House. Since there are voices objecting to the withdrawal of the Resolution, I am putting it to the House now. The qutstion is:

> "This House calls upon the Government to set up a petro-chemicals unit at Begusarai (Bihar) without any delay."

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, let us be clear. Are you putting the withdrawal motion or the main Resolution to the vote of the House?

MR. CHAIRMAN: Withdrawal is always done with the pleasure of the House. When that is objected to, then the rule is this: If objection is there to withdrawal, then, the rule

is, the main motion or the main Resolution has to be put to the vote of the House.

SHRI GEORGE FERNANDES : So now it is the Resolution which you are now going to put to vote.

MR. CHAIRMAN: Yes. It is the Resolution, not the motion for withdrawal.

SHRI P. C. SETHI: Sir, may I make a submission? Sir, when a motion for withdrawal has come, the normal practice is this. The only question is this that because it has become the property of the House, she cannot withdraw it on her own. The House has to give its consent to withdraw the same.

17 hrs.

MR. CHAIRMAN: The rule is that a Member who has made a motion may withdraw the same by leave of the House. But if any dissenting voice be heard or a Member rises to continue the debate, the Speaker shall forthwith put the motion.

SHRI P. C. SETHI: Now the motion before you is the motion for withdrawal of the resolution.

SOME HON. MEMBERS: No.

SHRI GEORGE FERNANDES: There is no motion for withdrawal before the House. It is the question of seeking leave of the House to withdraw the motion. If there is a dissenting voice and if there are Members in the House who believe that the motion itself should be decided and if the leave is denied, or in other words if their is any single dissenting voice, the motion itself should be put to the vote of the House. The only motion before the House is the resolution and not the withdrawal motion. That may be put now.

MR. CHAIRMAN: I am putting the motion again to the vote of the House. The question is:

"That this House calls upon the Government to set up a petro-chemicals unit at Begusarai (Bihar) without any delay."

Those in favour may say aye.

SOME HON. MEMBERS: Aye.

MR. CHAIRMAN: Those against may say No.

SEVERAL HON. MEMBERS: No.

MR. CHAIRMAN: Noes have it.

SOME HON. MEMBERS: No, Ayes have it.

MR. CHAIRMAN: All right, Division. Let the lobbies be cleared.

17.05 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MR. SPEAKER: The lobbies have now been cleared. The question is:

"This House calls upon the Government to set up a petro-chemicals unit at Begusarai (Bihar) without any delay."

Those in favour will please say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS: 'Aye'.

MR. SPEAKER: Those against will please say 'No'.

SOME HON. MEMBERS: 'No'.

MR. SPEAKER: I think the 'Noes' have it. The 'Noes' have it.

SOME HON. MEMBERS: 'Ayes' have it.

MR. SPEAKER: Iet the slips be distributed.

The Lok Sabha devided:

Division No. 5]

17.00 hrs.

AYES

Acharia, Shri Basudeb

Balan, Shri A. K.

Basu, Shri Chitta

Bhattacharya, Shri Sushil Kumar

Chakraborty, Shri Satyasadhan

Chaudhury, Shri Tridib

Choubey, Shri Narayan

Choudhury, Shri Saifuddin
Dandavate, Prof. Madhu
Fernandes, Shri George
Giri, Shri Sudhir Kumar
Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
Halder, Shri Krishna Chandra
Hannan Mollah, Shri
Hasda, Shri Matilal
Horo, Shri Nirel Enem
Kodiyan, Shri P. K.
Kunhambu, Shri K.
Madhukar, Shri Kamla Mishra
Maitra, Shri Sunil
Mandal, Shri Dhanik Lal
Mishra, Shri Satyagopal
Mohammed Ismail, Shri
Mukherjee, Shrimati Geeta
Mukherjee, Shri Samar
Parulekar, Shri Bapusaheb
Paswan, Shri Ram Vilas
Pathak, Shri Anand
Rajan, Shri K. A.
Saha, Shri Gadadhar
Satya Deo Singh, Prof.
Shailani, Shri Chandra Pal
Syed, Shri Masudal Hossain
Tur, Shri L. S.
Verma, Shri R. L. P.
Zainal Abedin, Shri

NOES

Ahmad, Shri Md. Kamaluddin
Anuragi, Shri Godil Prasad
Athare, Shri Chandra Bhan Balaji
Baitha, Shri D. L.
Bansi Lal, Shri
Banwari Lal, Shri
Bhagwan Dev, Shri
Bhardwaj, Shri Parasram
Birender Singh Rao, Shri
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandulal
Choudhari, Shrimati Usha Prakash
Chouhan, Shri Fatebhanu Singh
Daga, Shri Mool Chand
Dalbir Singh, Shri
Das, Shri A. C.
Dhandapani, Shri C. T.
Digvijay Sinh, Shri
Ekka, Shri Christopher
Era Mohan *alias* Ram Mohan R., Shri
Fernandes, Shri Oscar
Gadgil, Shri V. N.
Gehlot, Shri Ashok
Ghorpade, Shri R. Y.
Gohil, Shri G. B.
Gufran Azam, Shri
Gurbinder Kaur, Shrimati
Hakam Singh, Shri
Jain, Shri Virdhi Chand
Jaideep Singh, Shri
Khan, Shri Arif Mohammad
Krishna Pratap Singh, Shri
Krishna, Shri S. M.
Laskar, Shri Nihar
Mahabir Prasad, Shri
Mahala, Shri R. P.
Mahendra Prasad, Shri
Makwana, Shri Narsinh
Manphool Singh, Shri
Meena, Shri Ram Kumar
Mishra, Shri Hari Nath
Nadar, Shri A. Neelalohithadasan
Nagaratnam, Shri T.
Naikar, Shri D. K.
Nihal Singh, Shri
Pahadia, Shri Jagannath
Pandey, Shri Kedar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Panigrahi, Shri Chintamani
Pardhi, Shri Keshaorao.
Patel, Shri Amrit
Patel, Shri C. D.
Patel, Shri U. H.
Patil, Shri Balasaheb Vikhe
Patil, Shri Shivraj V.
Patil, Shri Vasantrao
Patil, Shri Veerendra
Quadri, Shri S. T.

Ranjit Singh, Shri
Rao, Shri Jalagam Kondala
Rao, Shri M. Satyanarayana
Raut, Shri Bhola
Ravani, Shri Navin
Rawat, Shri Harish
Reddy, Shri G. Narsimha
Sahi, Shrimati Krishna
Sethi, Shri Prakash Chand
Shanmugam, Shri P.
Shantaram, Shri
Sharma, Shri Nand Kishore
Sharma, Shri Vishwa Nath
Shivkumar Singh, Shri
Sidnal, Shri S. B.
Solanki, Shri Babu Lal
Sontosh Mohan Dev, Shri
Sparrow, General R. S.
Tayyab Husain, Shri
Tewari, Shri Chandra Bhal Mani
Tripathi, Shri R. N.
Uike, Shri Chhotelal
Venkataraman, Shri R.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Verma, Shri Jai Ram
Vijaya Bhaskara, Shri K.
Vyas, Shri Girdhari Lal

MR. SPEAKER: The result of the Division is:

Ayes: 36;

Noes: 85

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: Now there is the second resolution by Shri Sudhir Kumar Giri. We have to fix up the time for discussion for this resolution. Shall we fix two hours for this?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: Mr. Sudhir Kumar Giri, now you can move your resolution.

17.10 hrs.

RESOLUTION *RE* TAKING OVER OF WHOLESALE TRADE IN CERTAIN ESSENTIAL COMMODITIES

SHRI SUDHIR KUMAR GIRI (Contai): Mr. Speaker, with your permission I beg to move:

> "This House notes with grave concern the abnormal rise in prices of all essential commodities of human life, such as food-grains, pulses, edible oils, cloth, kerosene, coal, etc. in the country ranging between 20 to 40 per cent. within a short span of time and calls upon the government to take over wholesale trade and curb the price rise by ensuring supply of all the essential commodities at reduced prices through fair price shops."

MR. SPEAKER: Some amendments have been given notice of. But you may now continue.

SHRI SUDHIR KUMAR GIRI: Before starting my arguments in support of my resolution, I send my respects through you to the people who have sent me to this august House. I remember their depressed and hungry faces. Their hunger is due to the price rise. The government at the Centre had changed several times but they have not taken proper steps to ameliorate the conditions of millions of people who live below the poverty line. Those who were in power in 1971 promised that poverty would be removed. But the government records show that in 1977 the number of persons who lived below poverty line increased from 40 per cent to 70 per cent. In 1977 the government changed and under the new government these people were not able to procure the minimum necessities of life and I shall put forward through you to the House how the price rise had taken place in recent months.

In calculating the price rise I have taken the year 1970-71 as the base